

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

224/2018/25R7A

गोपाल बनावल कमला वगैर

2018/00224

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-1, 2, 3, 5

पेशी

श्री गोपाल बनावल

श्री सुलवीर सिंह चौधरी 3, 4

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

10/10
22

गोपाल बनाम कमला वगैरह (2018/00224)
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 3 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस कैम्प कोर्ट सुनवाई नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित किये थे उस समय केवल रेस्पोंडेन्ट ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। सर्वप्रथम अपीलांट को उपरोक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.06.2018 को हुयी जब रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांट के कब्जे काशत में दखलंदाजी की। जिस पर अपीलांट द्वारा न्यायालय में अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर उपरोक्त तथ्यों की जानकारी ली। जहाँ अभिभाषक ने अपीलांट को अवगत करवा कि कैम्प कोर्ट के तहत आदेश पारित किये थे इसलिए आगे अपील करने की आवश्यकता है। जिस पर नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने अपील पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट के द्वारा रामदेव से क्रय किया गया था जिसके पश्चात् से ही वह उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काशत चला आ रहा है परन्तु पश्चातवर्ती विक्रय-पत्र जो कि रामदेव की विरासत के आधार पर हुआ। जिससे रेस्पोंडेन्ट ने स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया और वही अपीलांट के कब्जे काशत में दखलंदाजी करने पर आमामा हो रहे है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काशतकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 अतिरिक्त आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 10.05.2018 को उपरोक्त वाद ग्राम खीरीया में राजस्व लोक अदालत के तहत प्रस्तुत होने पर बिना अपीलांट को सुने रेस्पोंडेन्ट द्वारा बताये गये झूठे कथनों के आधार पर विश्वास करते हुए निरस्त कर दिया। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 10.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र खीरीया में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये गये थे बाद तामील पत्रावली में सलंगन है। अपीलांट का यह कहना की कैम्प कोर्ट के नोटिस प्राप्त नहीं होना कलना गलत है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में देशी का उक्त कारण ही अंकित किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने दो प्रार्थना पत्र अस्थायी

Mu

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

224/18/225 RTA

जोपाल 4/5 कमला वर्ग

तारीख

2018/00224

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-1, 2 प्र. 4A-8

बन्धन व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जारी हुए

पेशी

श्री मों इबवाल

श्री तुलवीर सिंह चौधरी-3, 4

लगाव

नेपेघाड़ा पेश किये है पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2016 पेश किया तत्पश्चात दिनांक 12.03.2018 को पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किये है जो विधिक त्रुटि कारित की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिनांक 10.05.2018 जो आदेश पारित किये है विधि सम्मत है इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर गियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्कों के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी खरारा नम्बर 114 रकवा10 बीघा 18 विस्वा बाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खरारा नम्बर 114 रकवा10 बीघा 18 विस्वा बाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर